ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर राजस्थान अन्य राज्यों को बिजली दे रहा है- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने बीकानेर में सेवा संवाद कार्यक्रम में सेवा संकल्प यात्रा को संबोधित किया

बीकानेर, 24 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गत 25 वर्षों से एक-एक क्षण सेवा के लिए समर्पित रहा है। सेवा के इस संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक की सेवा संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा।

मुख्यमंत्री गुरूवार को बीकानेर में सेवा संवाद कार्यक्रम-सेवा संकल्प यात्रा अभियान को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सामाजिक सरोकार के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया है।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि एक लाख करोड़ रूपए की रामजल सेतु लिंक परियोजना में 41 हजार करोड़ रूपए के कार्य प्रगति पर हैं।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को बीकानेर में सेवा संवाद कार्यक्रम-सेवा संकल्प यात्रा अभियान को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की दशकों से अटकी 10 अंतर-राज्यीय परियोजनाओं का समाधान किया। इनमें राजस्थान की पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए चार परियोजनाएं-रामजलसेतु, यमुना जलसमझौता, नर्मदा समझौता और किशाऊ बहुद्देश्यीय बांध परियोजना शामिल हैं। इनमें 1 लाख करोड़ रुपये लागत की रामजलसेतु लिंक परियोजना में लगभग 41 हजार करोड़ रुपये के कार्य किए जा रहे हैं। वहीं, 35 हजार करोड़ रुपये की यमुना जलपरियोजना को धरातल पर तेजी से उतारा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और आज राजस्थान अन्य राज्यों को बिजली दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने बीकानेर में वेटरनरी कॉलेज में सेवा संकल्प कार्यक्रम के तहत आयोजित हो रही बाइक रैली के राइडर्स के साथ हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद को वीसी के माध्यम से देखा। मुख्यमंत्री ने बाइक राइडर्स से संवाद किया तथा उनके अनुभव जाने। उन्होंने कलश यात्रा और वडनगर से वाराणसी जा रही बाइक रैली को रवाना किया। इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, विधायकगण, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

ट्रंप दंभ भर रहे हैं, शी के साथ उनकी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बीसवीं सदी और उसके बाद की दुनिया को बदल देने वाली बुश-गोर्बाचेव मुलाकात या माओ त्से तुंग और रिचर्ड निक्सन के बीच हुई ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी शिखर वार्ता के स्तर तक नहीं पहुँच पाएगी।

फिलहाल, ट्रंप और शी की इस मुलाकात के नतीजों पर दुनिया की नज़र रहेगी, कि इसका आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के भविष्य और इसके संभावित हानिकारक प्रभावों पर क्या असर पड़ता है। यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब एआई टूल्स के बहुत तेजी से विकास से पैदा होने वाले संभावित खतरों को लेकर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की जा रही हैं।

पहले से ही ऐसे प्रमाण सामने आ चुके हैं कि बिना नियंत्रण के एआई दुनिया में कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। ओपन एआई मॉडल के एक बेकाबू "एजेंट" ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के आईटी सिस्टम में घुसपैठ की और कई स्तरों पर उसके कामकाज को पूरी तरह ठप कर दिया। कुछ समय पहले, एआई के क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों और उनके सबसे सक्षम शोधकर्ताओं ने भी चेतावनी दी थी कि एआई में मानवता को नष्ट करने की क्षमता हो सकती है।

इसी कारण उम्मीद थी कि दोनों वरिष्ठ नेता परिपक्व राजनेताओं की तरह व्यवहार करेंगे और विनाशकारी क्षमता वाली इस टैक्नॉलजी के विकास को सीमित करने पर सहमत होंगे। लेकिन शी जिनपिंग और डॉनल्ड ट्रंप दोनों ही इस आशंका से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि एआई के विकास पर किसी भी तरह

- **विशेषज्ञों का कहना है, ट्रंप और शी मीटिंग में एआई पर नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय होना मुश्किल है।**

का नियंत्रण लगाने से दूसरा पक्ष महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त हासिल कर सकता है।

इसलिए यह डर बना हुआ है कि दोनों नेता एआई मॉडल और एआई उत्पादों के नए उत्पाद तथा नई क्षमताएं विकसित करने के बारे में किसी भी तरह की सहमति नहीं बना पाएंगे।

यह स्थिति शीत युद्ध के दौर की याद दिलाती है, जब परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति को देखते हुए सोवियत नेताओं और उनके अमेरिकी समकक्षों ने परमाणु हथियारों के विकास और तैनाती को लेकर कुछ समझौते किए थे। जो समझौता हुआ था, उसे लंबी बातचीत के बाद "स्टार वार्स आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी" के नाम से जाना गया।

यह समझौता हाल तक लागू रहा और एक तरह से आज भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल और उनकी तैनाती के नियम तय करता है।

एआई के अलावा, दोनों नेता आपसी व्यापार और टैरिफ, यानी आयात शुल्क पर भी चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इन मुद्दों पर अमेरिका की स्थिति चीन की तुलना में काफी कमज़ोर है, जबकि चीन नौ साल पहले की तुलना में अब कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। चीन को अमेरिकियों पर अपनी ताकत का अहसास हो गया है, जिसे डॉनल्ड ट्रंप ने हाल ही में तब परखा था, जब उन्होंने अमेरिका को होने वाले चीनी एक्सपोर्ट पर भारी टैरिफ लगा दिया था।

चीन को केवल इतना करना था कि उसने अमेरिका को "रेअर अर्थ मिनरल्स" और उनसे बने उत्पादों का निर्यात रोक दिया और इसके तुरंत बाद डॉनल्ड ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इस बार नतीजा यह हो सकता है कि अमेरिका को अपनी सोच बदलनी पड़े और टैरिफ तथा बाजार तक पहुँच के मामले में चीन की कुछ मांगों को मानना पड़े।

अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपतियों के विपरीत, जिन्होंने देश की पिछली प्रतिबद्धताओं और नीतियों का सम्मान किया था, डॉनल्ड ट्रंप को अपने पूर्ववर्तियों या अतीत की अमेरिकी सरकारों के रूख से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए शी जिनपिंग जैसे मजबूत नेता के सामने डॉनल्ड ट्रंप ताइवान के मुद्दे पर चीन के दबाव के आगे झुक सकते हैं।

इसके अलावा, शी जिनपिंग की राजनीतिक स्थिति डॉनल्ड ट्रंप की तुलना में अधिक मजबूत है। डॉनल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में हैं और अपने देश में बढ़ती कीमतों, खासकर तेल की कीमतों, के कारण उनकी लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है। संवैधानिक रूप से वे अब "लेम डक प्रैसिडैंट" (कार्यकाल के आखिरी दौर में कमज़ोर राष्ट्रपति) हैं और आमतौर पर अगले कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में, ट्रंप अपने वर्तमान राजनीतिक दबाव और सोच के कारण ऐसा अजीब कदम उठा सकते हैं, जिसके बारे में कोई दूसरा अमेरिकी राष्ट्रपति शायद सोचता भी नहीं।

न्यूयॉर्क में चल रहे यूएनजीए सत्र की तुलना में शी जिनपिंग और डॉनल्ड ट्रंप के बीच वॉशिंगटन में होने वाली शिखर वार्ता का इंतजार दुनिया किसी नई और स्पष्ट वैश्विक दिशा के लिए नहीं कर रही है। इसके बजाय, इस बैठक को लेकर सबसे बड़ी दिलचस्पी इसकी पूरी तरह अनिश्चित प्रकृति और इससे निकलने वाले संभावित, सिद्धांतहीन परिणामों को लेकर है।

सीजेपी का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चलाने की मांग को भी बल मिला है।

आज राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार को "सबसे बड़ा देशद्रोही" बताते हुए, उन्हें भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया।

सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगें रखीं। पहली, कुमार को पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाहियों शुरू की जाए तथा कथित अवैध कार्रवाइयों के आदेश देने वाले व्यक्ति का नाम सार्वजनिक किया जाए। दूसरी, आगामी सभी चुनावों को तत्काल रोका जाए और एसआईआर की पूरी निर्णय प्रक्रिया की जांच के लिए एक स्वतंत्र जाँच आयोग का गठन किया जाए। और तीसरी, चुनाव आयोग के पुनर्गठन के लिए नया कानून बनाया जाए, ताकि जनता का उस पर विश्वास कायम हो सके।

क्या ज्ञानेश दूसरे धर्मेन्द्र प्रधान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी द्वारा लंबे समय से कही जा रही बात की पुष्टि की और उसे स्वीकार किया है। राहुल ने सवाल किया कि भारतीय चुनावी लोकतंत्र की एक बुनियादी ताकत सत्ता विरोधी लहर है जो भाजपा के खिलाफ आखिर गायब कैसे हो जाती है। उन्होंने कहा कि सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों, श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंह और राजीव गांधी, तक सत्ता विरोधी लहर से नहीं बच सके। विदेशों में भी दो ही देश है, जहां "एंटी इन्कम्बैंसी" नहीं दिखी -वो हैं सद्दाम हुसैन का ईराक, और नॉर्थ कोरिया। समयक्रम का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाए जाने के बाद ही असहमति पत्र लिखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अलंद और मधेपुरा में 'वोट चोरी' का खुलासा करने के बाद दोनों के पत्र लिखे जाने का समय एक संयोग है। राहुल ने कहा, इसकी शुरुआत 21 दिसंबर, 2023 को एक कानून पारित किए जाने के साथ हुई, जब प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कानूनी संरक्षण दिया और उन्हें कानूनी व्यवस्था से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून मुख्य चुनाव आयुक्त को जांच से संरक्षण देता है। नए मतदाताओं के लिए पंजीकरण कराना कितना मुश्किल है, इस सवाल के जवाब में गांधी ने कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि "जैन ज़ी" को मतदान का अधिकार मिले, क्योंकि भाजपा जानती है कि वे उसे वोट नहीं देंगे। ज्ञानेश कुमार, जिन्हें कुछ लोग धर्मेन्द्र प्रधान द्वितीय के रूप में देख रहे हैं, अब सरकार के कुछ वर्गों में एक बोझ के रूप में देखे जा रहे हैं। सुझाव दिए जा रहे हैं कि मोदी-शाह को अपना नुकसान कम करना चाहिए और उन्हें हटा देना चाहिए, अन्यथा पूरी सरकार पर हमले जारी रहेंगे।

'खाटूश्याम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पार्षद लक्ष्मी देवी की ओर से मत देने के लिए तय किया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि पूर्व में डाले गए मतों के आधार पर परिणाम घोषित किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया कि चुनाव प्रक्रिया को प्रत्येक निर्वाचित पार्षद के मतदान करने तक रोककर रखना नियमों के अनुरूप नहीं है।

'वोट चोरी से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संस्थागत ढांचा इसमें रुचि नहीं रखता था... गांधी ने आरोप लगाया, 'वोट चोरी' से 'कानून चोरी' होती है... 'कानून चोरी' से 'संस्था चोरी' होती है-संस्थाओं की चोरी। यही वह श्रृंखला है, जो सामने आई है।

'राजस्थान रॉयल्स टैक्स ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संचालक कंपनी को प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिस पर कंपनी संचालकों ने आपत्ति जताई कि वे दो जगहों पर अपने कार्यालय का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते। राजस्थान रॉयल्स की ओर से कहा गया कि, राज्य कर विभाग के अधिकारियों के इस आदेश के खिलाफ वे जीएसटी ट्रिब्यूनल में अपील दायर करेंगे, परंतु तब तक जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन ही नहीं हुआ था। राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने राजस्थान रॉयल्स को नोटिस जारी करते हुए यह भी कह दिया कि, चूंकि राजसथान रॉयल्स उन्हीं के आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं, इसलिए उन्हें "बिग ट्री" के साथ टिकट बेचान के अनुबंध पर भी टैक्स देना पड़ेगा। इस पर राजस्थान रॉयल्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर वर्ष 2024 में ही अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी थी। इस मामले में 23 सितंबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि, संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत, अगर दो राज्यों के बीच जीएसटी को लेकर विवाद हो तो इसका निस्तारण जीएसटी काउंसिल को करना होगा, जहां पर कंपनी ने प्रस्ताव भेजा हुआ है, जो कि लंबित है। राजस्थान रॉयल्स ने यह भी कहा कि, उनके मैच सिर्फ जयपुर अथवा राजस्थान में ही नहीं होते हैं, बल्कि सभी राज्यों में होते हैं। परंतु हैरानी की बात है कि किसी भी अन्य राज्य ने उन्हें टिकट बेचान पर दूसरी बार टैक्स लगाने का नोटिस नहीं दिया, इस पर अदालत ने टिप्पणी की, "राजस्थान सरकार इकलौती ऐसी सरकार है, जो गृह राज्य की टीम पर अतिरिक्त टैक्स वसूलने का काम कर रही है।" अदालत ने कहा कि राज्य सरकार, क्या चाहती है, क्रिकेट टीम राजस्थान में पधारे या बाहर पधारे।

हिंद महासागर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दरों और समुद्री बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी हो सकती है तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव बढ़ सकता है। भारतीय नौसेना यूँ भी इन जलक्षेत्रों पर करीबी नजर रखती ही है; लेकिन व्यापक अस्थिरता से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए अधिक सैन्य मौजूदगी और कूटनीतिक प्रयासों की जरूरत बढ़ जाएगी। इस बीच कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर, अमेरिका और ईरान के बीच, कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में, बातचीत हुई है। तेहरान ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिनमें नौसैनिक नाकाबंदी समाप्त करना, फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करना और सभी मोर्चों पर शत्रुता समाप्त करना शामिल है। मध्यस्थ अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं, लेकिन आपसी अविश्वास और नई धमकियों के कारण स्थायी समाधान अभी भी दूर है। सफवी की चेतावनी यह दर्शाती है कि यह युद्ध किस तरह एक व्यापक समुद्री संघर्ष में बदलने का जोखिम पैदा कर सकता है। यह केवल बयानबाजी के रूप में प्रतिरोध तक सीमित रहता है या वास्तविक संघर्ष बढ़ने का संकेत देता है, यह सभी पक्षों के संयम और कूटनीतिक प्रयासों में प्रगति पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com **कोटा कार्यालय:**-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 **बीकानेर कार्यालय:**-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 **उदयपुर कार्यालय:**-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 **अजमेर कार्यालय:**-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय:** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908